

प्रेषक,

डॉराकेश कुमार,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक २५ नवम्बर, 2010

विषय:- मैं ० अडप्ट लाईफ केयर को ग्राम माधोपुर हजरतपुर, परगना भगवानपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना के फलस्वरूप सम्पर्क मार्ग का निर्माण किये जाने हेतु ०.०३६७ है० भूमि क्य की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-1494/भूमि व्यवस्था-भू क्य, दिनांक-15.1.2007 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, मैं ० अडप्ट लाईफ केयर को ग्राम माधोपुर हजरतपुर, परगना भगवानपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना के फलस्वरूप सम्पर्क मार्ग का निर्माण किये जाने हेतु ०.०३६७ है० भूमि क्य की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जर्मिंदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति/सहमति एवं आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्या-82 के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1— केता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अर्ह होगा।

2— केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3— केता द्वारा क्य की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (सम्पर्क मार्ग का निर्माण) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्य किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगा।

4— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्य से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकरणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6— शासन द्वारा दी गई भूमि क्य की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7— क्य की जाने वाली भूमि का भू उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर जी0डी0आई0डी0सी0आर0-2005 में दिये गये नियमों/मानकों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्लान के अनुसार सङ्क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8— ईकाई द्वारा क्य की जाने वाली भूमि का उपयोग, उद्योग के कार्य स्थल से मुख्य मार्ग तक सम्पर्क मार्ग/सङ्क मार्ग के लिए ही किया जायेगा।

9— ईकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

10— प्रस्तावित स्थल पर, अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित ईकाई का होगा।

11— सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगे।

12— किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्य के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

13— भूमि का विक्य अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्य किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

14— योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/ संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियों/स्वीकृतियों प्राप्त कर ली जायेगी।

15— उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन हाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में, जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा०राकेश कुमार)  
सचिव।

पृष्ठ सं-२५३ / समिति कित / 2010

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन।
- 3— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4— निदेशक, उद्योग विभाग औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर देहरादून।
- 5— मै० अडप्ट लाईफ केयर, 711/66, मथुरा विहार रुड़की, जिला हरिद्वार।
- 6— निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 7— प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
- 8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बंडोनी)

अनुसचिव।